

## v/; k; -I i Lrkouk

### 1.1 bl ifronu ds l EclU/k ea

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी), भारत सरकार एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से सम्बन्धित वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित है।

यह अध्याय विभागों और सम्बन्धित संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सार के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी) के अधीन विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन इन विभागों और पी एस यू के लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों की अनुवर्ती कार्यवाही भी सम्मिलित है। अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित हैं।

### 1.2 ys[ kki jh{kk grq i kf/kdkj

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तथा सी ए जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। सी ए जी, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी ए जी के (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13<sup>1</sup> और 17<sup>2</sup> तथा पी एस यू की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 के तहत करता है।

### 1.3 ys[ kki jh{kk dh ; kstuk vkj l pkju

सी ए जी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्तों और व्यवहारों के अनुरूप लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों के जोखिम के आँकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है।

### 1.4 ys[ kki jhf{kr bdkb; ka dh #i js[ kk

#### 1.4.1 njl pkj foHkkx (Mh vks Vh)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार<sup>3</sup> है। विभाग आवृत्ति का आबंटन भी करता

<sup>1</sup> (i) भारत के समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी लेन-देन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखे, तुलनपत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

<sup>2</sup> संघ अथवा राज्य के किसी विभाग अथवा कार्यालय में रखे गये भण्डार एवं स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रतिवेदन

<sup>3</sup> डी ओ टी का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन

है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबन्धन करता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसार, विभाग विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में मूलभूत व मूल्यवर्धित सेवाएं देने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

► 0; ; fo' y\$kk.k

डी ओ टी के 2014-15 और पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका-1 में दी गई है:

rkfydk-1  
Mh vks Vh ds jktLo vks 0; ;

(₹ djkm+ e)

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व	1,20,547.63	17,400.92	18,902.00	40,113.76	30,624.18
व्यय	10,370.26	8,692.16	9,273.38	10,835.57	13,026.14

(स्रोत: डी ओ टी के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

rkfydk -2  
i klr ykbl d 'kY'd vks Li DV'e mi ; ksx i Hkkjka dk fooj .k

(₹ djkm+ e)

fooj .k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लाइसेंस शुल्क	10,286.43	11,790.93	11,456.48	14,628.47	12,358.29
स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार	3,432.47	5,192.30	5,679.19	6,883.67	1,7841.93 <sup>4</sup>
नीलामी राजस्व	1,06,264.73	-	1,722.24	18,267.18	-

(स्रोत: 2015-16 के लिए डी ओ टी का वार्षिक प्रतिवेदन)

दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2010-11 तथा 2013-14 के दौरान, विभाग की आय में वृद्धि हुई जोकि इन वर्षों में आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई प्राप्ति के कारण थी। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग का व्यय विगत चार वर्षों के दौरान स्थिर रूप से बढ़ा।

► nijl pkj {ks= dh l f{klr #ijs[kk

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक असाधारण वृद्धि देखी। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 846.32 मिलियन से बढ़कर 996.49 मिलियन हुई। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए समग्र विकास की स्थिति नीचे तालिका-3 में दी गई है।

<sup>4</sup> ₹ 17,841.93 करोड़ के स्पेक्ट्रम उपयोग चार्ज में नीलामी फीस भी सम्मिलित है।

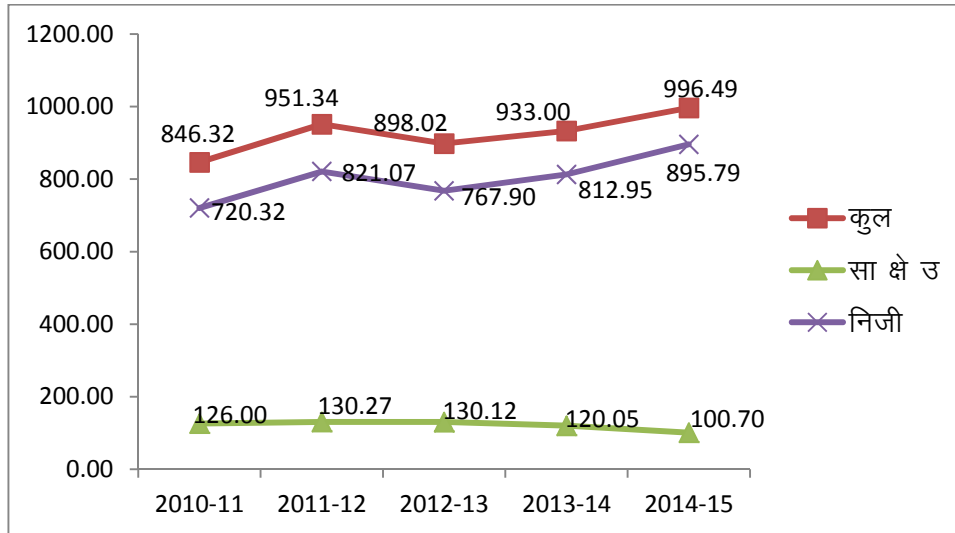
rkfydk-3  
nj l pkj {ks= ea of) dh fLFkfr

o"kz	mi HkkDrk (fey; u e)					l pkj ?kuRo (i fr'kr e)		
	dy	xkeh.k	'kgjh	ok; jykbu	ok; jy]l	l exl	xkeh.k	'kgjh
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55
2012-13	898.02	349.22	548.80	30.21	867.81	73.32	41.02	146.96
2013-14	933.00	377.74	555.26	28.49	904.51	75.23	43.96	145.78
2014-15	996.49	419.31	577.18	26.60	969.89	79.38	48.37	148.61

(स्रोत: ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन 2010-11 से 2014-15)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी है:

mi HkkDrk vk/kkj ea of) & futh cuke l ko]tfud {ks= ds mi Øe  
mi Ø'Drkv'adh l i]; k (fey; u e)



(स्रोत: ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि ऊपर ग्राफ से स्पष्ट है, कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में जोकि पिछले चार वर्षों के दौरान अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शा रही है, निजी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ता आधार महत्वपूर्ण है।

➤ {ks= dk fu; ked <kpk

Hkkj rh; nj l pkj fu; ked i kf/kdj .k (V'kb)

ट्राई की स्थापना, दरों में निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, जो पहले केन्द्र सरकार में निहित था, हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं को एक समान अवसर प्रदान करें, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करें तथा सभी को प्रौद्योगिकी लाभ दिलाने वाला हो। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई को अधिकार दिया गया है

- लाइसेंस के नियमों व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले सेवा गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- टैरिफ पालिसी निर्धारित करना एवं नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तों तथा सेवा प्रदाता को लाइसेंस के लिये नियम व शर्तों की अनुशंसा करना;
- टैरिफ पालिसी की मॉनिटरिंग, वाणिज्यिक तथा अंतःसंयोजन के तकनीकी पहलुओं से संबंधित मामलों पर विचार व निर्णय;
- काल राउटिंग एवं काल हैंडओवर के सिद्धांत;
- जनता के लिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं में चुनने की स्वतंत्रता एवं आसान पहुँच;
- बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिये विविध नेटवर्क ढांचों के कारण उत्पन्न संघर्ष का समाधान;
- विद्यमान नेटवर्क व प्रणालियों को और उन्नत करने की आवश्यकता; और
- सेवा प्रदाताओं में बातचीत तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत के लिए फोरम विकसित करना;

सरकार के दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा ब्राडकास्टिंग सेवाओं एव केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा मानते हुए ट्राई के अन्तर्गत लाया गया। ट्राई के लिए आवश्यक है कि वह या तो स्वयं या फिर लाइसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अथवा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से केबल सेवाओं के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर, सिफारिशें दे।

#### **njl pjk fookn fui Vku vkj vi hyh; U; k; kf/kdj .k (Vh Mh I S/)**

एक लाइसेंस प्रदाता और एक लाइसेंस धारक के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए तथा ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई और अपील के निपटान के लिए टी डी सैट की स्थापना ट्राई अधिनियम में 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक संशोधन के जरिए हुई थी।

#### **➤ njl pjk foHkkx dh egRoI w kZ bdkb; k;**

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (टी ई सी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान संस्थान (एन टी आई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन आई सी एफ) तथा टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) इकाई है, शामिल हैं।

#### **➤ I koHkkfed I ok nkf; Ro fuf/k (; w , I vks Q.M)**

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड) का गठन किया। यू एस ओ की आवश्यकताओं हेतु स्रोत सार्वभौमिक अभिगम उदगृहण (यू ए एल), जो कि विभिन्न लाइसेंसों के अर्न्तगत सभी संचालकों द्वारा अर्जित राजस्व का प्रतिशत था, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम, 2003 के पैरा 9बी के अनुसार, यू एस ओ फण्ड के लिये प्राप्त धन राशि को पहले भारत

की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय-समय पर ऐसी आय को निधि में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रूप से पूरा करने के उपयोग हेतु जमा कर सकती है। तदनुसार 31 मार्च 2015 तक यू एस ओ उद्गृहण के रूप में ₹ 66,118.04 करोड़ की राशि दूरसंचार विभाग (दू वि) द्वारा एकत्र की गई, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया था। दूरसंचार विभाग द्वारा इस राशि में से मात्र ₹ 26,983.47 करोड़ संसद के विनियोग द्वारा प्राप्त किये गये तथा 31 मार्च 2015 तक यू एस ओ फण्ड में जमा किये गये। इसमें वर्ष 2002-06 में लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड को 2008-09 में प्रतिपूर्ति किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित हैं जोकि यू एस ओ फंड के अन्तर्गत ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु थे।

➤ foHkkx ds iz kkl dh; fu; æ.k ea l koZtfud {ks= mi Øe (ih , l ; )

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पी एस यू का संक्षिप्त खाका नीचे दिया गया है:

Hkkjr l pkj fuxe fyfeVM

अक्टूबर 2000 में गठित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) दिल्ली और मुंबई को छोड़कर, देश के कोने-कोने में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक तकनीक उन्मुख कम्पनी है तथा जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैंडलाइन पर दूरभाष सेवायें, डब्ल्यू एल एल एवं जी एस एम मोबाइल, ब्राडबैंड, इन्टरनेट, लीज्ड सर्किट एवं लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 28,645.20 करोड़ था व इसे ₹ 8,234.09 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे तालिका-4 में वर्णित है:

rkfydk-4  
foxr rhu o"kkæ ea ch , l , u , y dk fu"i knu

o"kl	jktLo	0; ; (₹ dj kM+ ea)	vfHknkrk çd		
			ok; jykbu	crkj	dy
			(dj kM+ ea)		
2012-13	27,127.89	34,900.43	2.04	10.12	12.16
2013-14	27,996.35	34,929.60	1.85	9.47	11.32
2014-15	28,645.20	37,292.10	1.64	7.72	9.36

उपरोक्त डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि यद्यपि कम्पनी का राजस्व व व्यय दोनों ने ही विगत तीन वर्षों के दौरान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है, सभी तीनों वर्षों में व्यय की वृद्धि-दर राजस्व की अपेक्षा अधिक है। इसके अतिरिक्त, वायरलाइन व बेतार उपभोक्ता का अभिदाता बेस इस अवधि में विचारणीय रूप से कम हुआ है।

egkuxj VsyhQku fuxe fyfeVM

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) को एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 1986 में स्थापित किया गया था तथा दिल्ली व मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क का नियंत्रण, प्रबन्धन व प्रचालन के लिये उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा एवं जी एस एम मोबाइल सेवा का प्रमुख प्रदाता है। एम

टी एन एल पृथक सामान्य लाइसेंस करार के अन्तर्गत दिल्ली व मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवायें भी प्रदान कर रहा है। यह ब्रॉडबैंड व 3जी सेवायें भी प्रदान कर रहा है। सरकार ने वर्ष 1994 में 20 प्रतिशत अंश बैंक/उनके सहायक और वित्तीय संस्थानों में विनिवेश किये। एम टी एन एल आज की तारीख में एक सूचीबद्ध कम्पनी है और 56.25 प्रतिशत अंश सरकार के पास और शेष निजी अंशधारको के पास है। वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 3,821.06 करोड़ था और इसे ₹ 2,893.39 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे तालिका-5 में वर्णित है:

**rkfydk-5**  
foxr rhu o"kk&ea , e Vh , u , y dk fu"i knu

o"kl	jktLo	0; ; (₹ djkm+e)	vfHknkrk cd		
			ok; jykbu	crkj	dy
			(djkm+e)		
2012-13	3,714.08	9,015.82	0.34	0.50	0.84
2013-14	3,787.37	6,870.41	0.35	0.34	0.69
2014-15	3,821.06	6,723.48	0.36	0.35	0.71

कम्पनी के राजस्व ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान मामूली वृद्धि दर्शाई है। 2012-13 के दौरान व्यय थोड़ा अधिक था लेकिन बाद के वर्षों में इसने अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है। वायरलाइन उपभोक्ता के अभिदाता बेस ने 2012-13 से 2014-15 में प्रतिवर्ष मामूली वृद्धि दर्शाई है लेकिन वर्ष 2013-14 में बेतार उपभोक्ता के संबंध में 50 लाख से 34 लाख की विचारणीय कमी हुई। 2014-15 के दौरान मामूली वृद्धि थी।

**feyfu; e Vsyhdkkk fyfeVM (, e Vh , y)**

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) द्वारा मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) का निर्माण वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी के रूप में सबमेरिन केबिल परियोजना की स्थापना तथा आई टी समाधान के लिये, किया। वर्ष 2014-15 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 2.95 करोड़ था और इसने ₹ 0.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

**Hkkj rh; njj Hkk" k m | ksx fyfeVM (vkbz Vh vkbz fy)**

आई टी आई लिमिटेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बंगलूरु में अपने संचालन प्रारम्भ किये जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्काड में निर्माण सयंत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में आगे विस्तारित किये गये। कम्पनी का कुल राजस्व वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 659.25 करोड़ था तथा उसे ₹ 297.13 करोड़ की हानि हुई।

**Hkkj rh; njj l pkj i jke' khkrk fyfeVM (Vh l h vkbz , y)**

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की स्थापना, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से, विदेशी एवं घरेलू बाजारों में उचित विपणन रणनीति विकसित कर तथा अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कर अपने संचालनों में उत्कृष्ट होने के लिये 1978 में हुई थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 831.48 करोड़ था तथा इसने ₹ 21.37 करोड़ लाभ अर्जित किया।

#### rfeyukMq njl pkj fyfeVM (Vh Vh , y)

तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड वर्ष 1988 में निगमित गया था। यह टी सी आई एल, टी आई डी सी ओ व फूजीकुरा लिमिटेड, जापान का एक त्रिकोणीय संयुक्त प्रयास था। इसमें मुख्य अंशधारकों के अंश व्यवस्था है जिनमें कि टी सी आई एल का (49 प्रतिशत), तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का (14.63 प्रतिशत) और फूजीकुरा लिमिटेड जापान का (7.18 प्रतिशत) अंश है। बाकी अंश बैंकों व वित्तीय संसाधनों, प्राइवेट ट्रस्टों, एन आर आई व भारतीय जनता के पास है। यह दूरसंचार के लिये आप्टिकल फाइबर केबिल का निर्माण करती है। यह कम्पनी बी आई एफ आर को सन्दर्भित है व 21 जुलाई 2010 को पुनर्गठन के लिए एक योजना को संस्वीकृति प्रदान की गई थी। यह टेबलेट पी सी व एफ टी टी एच (फाइबर टू होम) घटकों में भी जाकर विविधता दिखाई। वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 20.48 करोड़ था व कम्पनी को ₹ 8.57 करोड़ की हानि हुई।

#### bāsyhtV dE; fud'sku fl LVe bāM; k fyfeVM (vkbz l h , l vkbz , y)

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल) को वर्ष 1987 में निगमित किया गया था। यह टी सी आई एल और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (डी एस आई आई डी सी) जो दिल्ली सरकार के अधीन एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें टी सी आई एल के पास 36 प्रतिशत अंश तथा डी एस आई आई डी सी के पास 40 प्रतिशत अंश है। कम्पनी प्रख्यात ब्राण्डों की हार्डवेयर वस्तुएँ जैसे कम्प्यूटर/दूरसंचार/आई टी आदि के व्यापार में संलिप्त है। यह कम्पनी विभिन्न संगठनों को जनशक्ति उपलब्ध कराती है तथा लाइसेंस धारकों द्वारा व्यक्तिगत समझौता के अंतर्गत प्रत्येक को शिक्षा उपलब्ध कराती है। यह कम्पनी हार्डवेयर वस्तुओं के वार्षिक अनुरक्षण का भी कार्य अपने हाथ में लेती है। वर्ष 2014-15 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 97.80 करोड़ था तथा ₹ 2.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

#### Vh l h vkbz , y-chuk Vksy jkM+fyfeVM

टी सी आई एल-बीना टोल रोड़ लिमिटेड, टी सी आई एल की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है तथा इसे 2012 में निगमित किया था। इस कम्पनी की संरचना, डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण पर आधारित ढांचागत परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया, यथा मध्यप्रदेश भारत में बीना एवं कुरवाई नगर के बीच टोल रोड़ परियोजना। कम्पनी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन अप्रैल 2014 में प्रारम्भ किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 वाणिज्यिक प्रचालन का पहला वर्ष है। कम्पनी का वर्ष 2014-15 में कुल राजस्व ₹ 4.97 करोड़ था एवं इसने ₹ 9.42 करोड़ की हानि का वहन किया।

#### Vh l h vkbz , y-y[kukMksu Vksy jkM+fyfeVM

टी सी आई एल-लखनाडोन टोल रोड़ लिमिटेड, जो भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है, को वर्ष 2013 में निगमित किया गया। यह एक विशेष उद्देश्य वाहन है जिसका गठन लखनाडोन टोल रोड़ परियोजना के विकास के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एम पी आर डी सी) के साथ रियायतग्राही अनुबंध के क्रियान्वयन के उद्देश्य से हुआ। सितम्बर 2011 में टी सी आई एल द्वारा एम पी आर डी सी के

साथ रियायतग्राही अनुबंध हुआ और अगस्त 2014 में टी सी आई एल, एम पी आर डी सी और कम्पनी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ ताकि टी सी आई एल के नाम को बदलकर कम्पनी का नाम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना की समाप्ति तक टी सी आई एल एक सहायक संगठन के रूप में काम करेगी और इसे कम्पनी को सौंप देगी। कम्पनी ने अभी तक राजस्व अर्जित करना शुरू नहीं किया है क्योंकि टोल रोड़ का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है परन्तु ₹ 0.02 करोड़ की हानि हुई है।

#### Hkkjr ckMcM usVodZ fyfeVM (ch ch , u , y)

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), जो एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) है, को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) निष्पादित करने हेतु 2012 में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया। बी बी एन एल को देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के मध्य सम्पर्कता अन्तर को भरने के लिये अतिरिक्त फाइबर बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्राडबैंड सम्पर्कता सुनिश्चित करेगा। कम्पनी का वर्ष 2014-15 में कुल राजस्व ₹ 11.33 करोड़ था और इसने ₹ 0.29 करोड़ की हानि उठाई।

#### gfelQh; j i ksi VhZt bfiM; k fyfeVM ( , p i h vkbZ , y)

हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल), जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, को 2005 में निगमित किया गया था और 18 मार्च 2014 से यह सरकारी कम्पनी हो गई। भारत सरकार व मैसर्स पानाटोन फीनवेस्ट लिमिटेड तथा अन्य टाटा कम्पनियों के मध्य 13 फरवरी 2002 को अंश क्रय करार के क्लॉज़ 7.10 व अंशधारक करार के क्लॉज़ 4.7 के अनुसार कम्पनी को निगमित किया गया था, जिसमें वी एस एन एल के गैर-निवेश के समय पहचान की गई अधिशेष भूमि कम्पनी में विसम्बद्ध हो गयी। दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार 51.12 प्रतिशत इक्विटी अंश का स्वामित्व रखती है और बाकी बचे हुये अंश मैसर्स टाटा कैपिटल लिमिटेड एवं आपताब निवेश कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व में है। कम्पनी की दत्त अंश पूँजी ₹ 5.00 लाख है। कम्पनी ने वर्ष 2014-15 में कोई राजस्व अर्जित नहीं किया है एवं इसने ₹ 3.73 लाख की हानि उठाई है।

#### 1.4.2 Mkd foHkx (Mh vks i h)

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख से अधिक डाकघर हैं तथा यह देश के दूरस्थ किनारों तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं जिनमें धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती हैं। यह सैन्य एवं रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचारियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन के संवितरण के कार्य में भी लगी है। डाक विभाग ने भी सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जिम्मेदारी ली है।



## foRrh; fu"iknu

डाक विभाग के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका-6 में दर्शाया गया है :

rkfydk -6  
Mkd foHkkx dh jktLo ikflr; k; , oajktLo 0; ;

(₹ djKM+ ea)

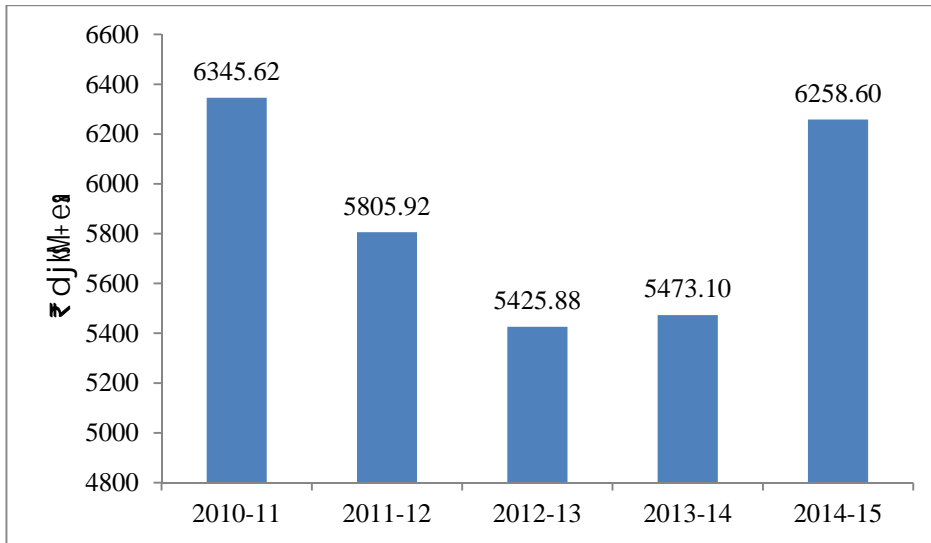
o"KZ	jktLo ikflr; k;	ol fy; k; <sup>5</sup>	jktLo 0; ;	?kkVk (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010-11	6,962.33	485.72	13,793.67	6,345.62
2011-12	7,899.35	458.64	14,163.91	5,805.92
2012-13	9,366.50	688.77	15,481.15	5,425.88
2013-14	10,730.42	593.19	16,796.71	5,473.10
2014-15	11,635.98	661.98	18,556.56	6,258.60

(स्रोत: डी ओ पी के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के विनियोजन लेखे)

विभाग की आय “राजस्व प्राप्तियों” एवं “वसूलियों” के रूप में है।

2014-15 में डाक सेवाओं<sup>6</sup> पर ₹ 6,258.60 करोड़ का घाटा था। विभाग द्वारा घाटे का मुख्य कारण वेतन में वृद्धि, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवा व अन्य प्रभारों में बढ़े हुए व्यय के कारण कार्यचालन व्ययों में वृद्धि, बताई गई। 2010-11 से 2014-15 की अवधि में डाक सेवाओं में घाटे की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:

Mkd I okvka ea ?kkVk



### 1.4.3 byDVkfudl , oal upuk i kS| kfxdh foHkkx (Mh Ā vkĀ Vh okĀ)

डी ई आई टी वाई, इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ई आई टी वाई की परिकल्पना, विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में परिवर्तन हेतु यंत्र के रूप में भारत का ई-विकास करना है।

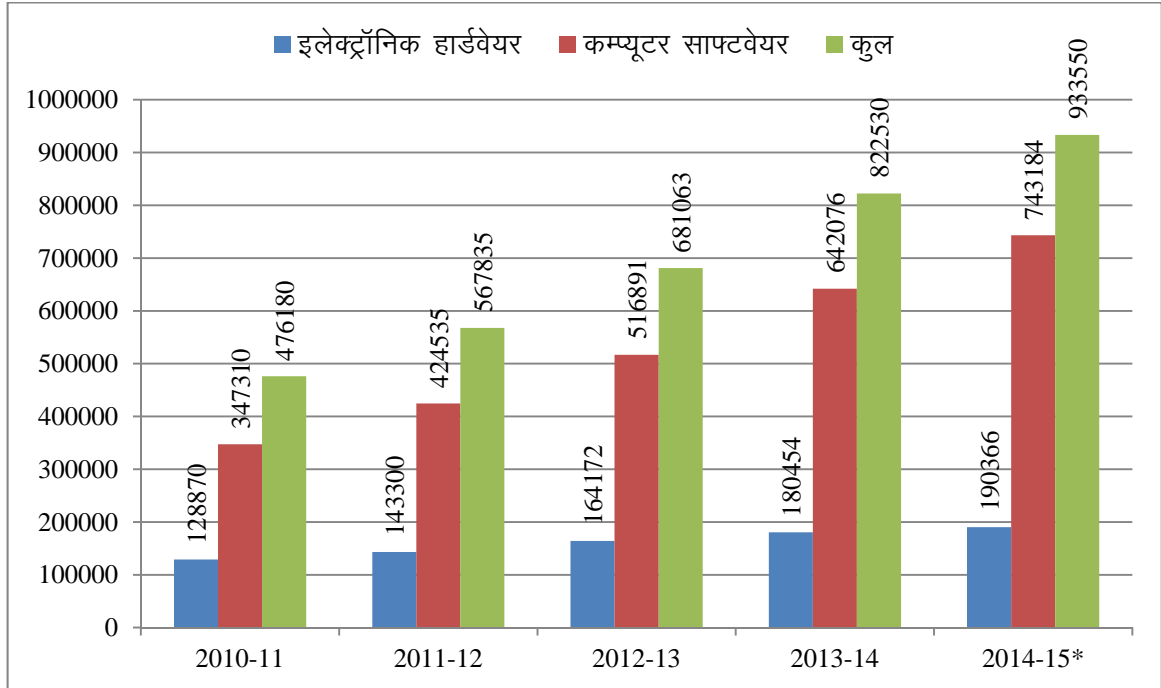
<sup>5</sup> यह दूसरे सरकारों तथा संघ सरकार के विभागों को प्रदान की गई सेवाओं के मद में वसूलियों को दर्शाता है।

<sup>6</sup> घाटे की गणना राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर पर की गयी है यथा, {₹11,635.98 + ₹661.98} - ₹18,556.56}

भारतीय आई टी उद्योग भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता रहा है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी-आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि खाका नीचे चार्ट में दिया गया है:

byDVkkuDI , oa vkbz Vh mRi knu

(₹ djkm+e)



(स्रोत: डी ई आई टी वार्ड का वार्षिक प्रतिवेदन)

\* अनुमानित आँकड़ें उद्योग संघ, मंत्रालय एवं अन्य संगठनों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं।

विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी-आई टी ई एस उद्योग के सतत् समग्र विकास का मुख्य कारण तुलनात्मक रूप से सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं में अधिक वृद्धि है जो कि अधिकांशतः निर्यात संचालित एवं आई टी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती है।

अपने कार्यों के निर्वहन हेतु डी ई आई टी वार्ड को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष डी ई आई टी वार्ड द्वारा किया गया व्यय, तालिका-7 में दिया गया है।

rkfydk - 7

Mh bZ vkbz Vh okbz l s l cf/kr vupku ds l ki qk 0; ;

(₹ djkm+e)

वर्ष	व्यय	अनुदान
2010-11	3,719	3,129
2011-12	3,048	2,074
2012-13	3,051	1,903
2013-14	3,052	2,166
2014-15	3,929	3,583
द्वारा	16,799	12,855

(स्रोत: डी ई आई टी वार्ड के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के विनियोजन लेख)

डी ई आई टी वाई के अधीन पाँच संगठन<sup>7</sup> और सात स्वायत्त सोसायटी<sup>8</sup> के अतिरिक्त दो संलग्न कार्यालय नामतः मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) हैं।

**jk"Vh; | |puk foKku dlnz (, u vkbz | h)**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई-शासन की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में (अ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत् श्रृंखला प्रदान करता है।

**ekudhdj .k, ijh{k.k vkj xq koRrk iæk.ku funs'kky; (, | Vh D; | | h)**

वर्ष 1980 में स्थापित एस टी क्यू सी, अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने तथा आई टी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये डी ई आई टी वाई आदेश पत्र के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है।

**> foHkkx ds iz kkl fud fu; æ.k ds vllrxr | kozt fud {ks= mi Øe (ih , | ; |)**

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:

**ehfM; k y& , f'k; k**

मीडिया लैब एशिया, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत आम आदमी को आई सी टी के लाभ दिलाने के उद्देश्य से बनायी गयी गैर-लाभकारी कम्पनी है। मीडिया लैब एशिया के अनुप्रयोग क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाये, शिक्षा, आजीविका एवं विकलांगों के सशक्तिकरण में आई सी टी का उपयोग शामिल करते हैं। यह कम्पनी गारन्टी द्वारा सीमित है और इसके पास कोई अंश पूँजी नहीं है एवं इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के तहत सौंपी गयी है। कम्पनी विकास कार्य के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करती है। कम्पनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 67.64 करोड़ अर्जित किये हैं और सहायता अनुदान के द्वारा ₹ 67.59 करोड़ प्राप्त किये हैं।

**jk"Vh; | |puk foKku dlnz | ok; a bad (, u vkbz | h , | vkbj)**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक (एन आई सी एस आई) को सरकारी संगठनों को पूर्ण आई टी समाधान उपलब्ध कराने के लिये, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 की

<sup>7</sup> प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सी सी ए), साइबर अपीलीय प्राधिकरण (सी वाई ए टी), सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट-डिजाइन रजिस्ट्री, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई सी ई आर टी) और इन रजिस्ट्री

<sup>8</sup> कम्प्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षण एवं शोध (अरनेट), उच्च संगणना विकास केन्द्र (सी-डैक), इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी-मैट), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर), भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी आई) एवं इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नति परिषद (ई एस सी)

धारा 25 के अन्तर्गत 1995 में स्थापित किया गया था। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 902.45 करोड़ था और कर के बाद अधिशेष वर्ष में ₹ 52.55 करोड़ था।

### 1.5 ctV vkj 0; ; fu; k

डी ओ टी, डी ओ पी तथा डी ई आई टी वाई के संदर्भ में 2014-15 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश आगामी तालिका-8 में दिया गया है:

#### rkfydk-s

l pkj , oa l puk i kS| kfxdh ea-ky; ds v/khu rhu foHkxka dks fn; s x; s vupku (okM/M , oa pktM) rFkk muds }kj k fd; s x; s 0; ; dk foj .k

(₹ djkM+e)

Øe l d; k	ea-ky; /foHkx	vupku/fofu; kstu (vuqj d vupku l fgr)	dy 0; ;	(-) cpr/ (+) vkf/kD;
1.	दूरसंचार विभाग	18,319.74	13,026.14	(-) 5,293.60
2.	डाक विभाग	19,010.42	18,729.52	(-) 280.90
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3,929.12	3,583.10	(-) 346.02

(स्रोत: 2014-15 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)

### 1.6 ys[ kki jh{kk ifronuka ij vuprh/ dk; bkgh - (fl foy)

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सदन पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद, इसमें सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों पर की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही दर्शाते हुए, टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसा की, कि मार्च 1996 और आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों पर ए टी एन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के अन्दर, लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जायें।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्यवाही करने और पी ए सी को ए टी एन प्रस्तुत करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2015 की अवधि तक संघ सरकार (संचार व आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि अप्रैल 2016 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत तीन विभागों अर्थात् डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और डी ई आई टी वाई से सम्बंधित 12 अनुच्छेदों में ए टी एन लम्बित थे, जैसा कि ifj'k"V&I में वर्णित है।

## 1.7 ys[ kki jh{kk ifronuka ij vuprh/ dk; bkgh - (okf.kfT; d)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालक से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए, टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (सी आ पी यू) द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चयनित नहीं किया गया था। सी ओ पी यू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए, अनुशंसा की:

- पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पी एस यू से सम्बन्धित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में ए टी एन के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा
- समिति को संसद में प्रस्तुत किये गये सी ए जी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से छः माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, ए टी एन पर अनुवर्ती कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सी ओ पी यू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000 तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डी पी ई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी हेतु स्वयं डी पी ई में एक पृथक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार, अगस्त 2000 के बाद से सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी करने के लिए डी पी ई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सम्बंधित मंत्रालयों के अन्दर भी सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन प्रस्तुत करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के अन्दर सीएजी लेखापरीक्षा अनुच्छेद और पी ए सी की अनुशंसाओं पर लम्बित ए टी एन/ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। इस निर्णय (जुलाई 2010) को

संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संस्थागत तंत्र की अनुशंसा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एवं आई टी), दूरसंचार विभाग, के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड और मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से सम्बंधित वर्ष 2015 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि, अप्रैल 2016 की स्थिति में, 93 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में ए टी एन लम्बित थे, जिनमें से 11 अनुच्छेदों पर ए टी एन अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा *ijff'k"V-II* में वर्णित है।